



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



YOJANA MAGAZINE ANALYSIS (योजना पत्रिका विश्लेषण)

(आधारभूत संरचना)

(October 2023)

(Part I)

TOPICS TO BE COVERED

- संपादकीय: समय, गति और परिमाण
- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- स्मार्ट होती सड़क अवसंरचना
- रेल अवसंरचना

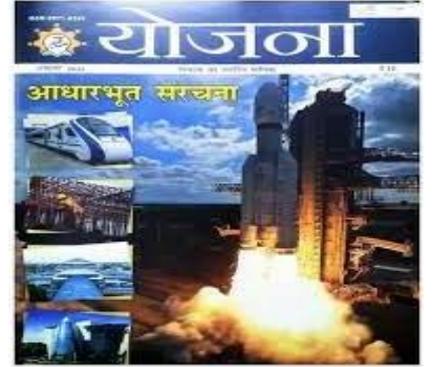
ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



संपादकीय: समय, गति और परिमाण (Scale)

- परिवहन की एक सुव्यवस्थित और समन्वित प्रणाली देश के सतत आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटीय नौवहन, हवाई परिवहन आदि कई माध्यम शामिल हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में परिवहन ने नेटवर्क के विस्तार और आउटपुट दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
- पूरे देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और अंतिम छोर तक पहुंच (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) के आधारभूत संरचना निर्माण की आवश्यकता थी।
- परिवहन की **मल्टी मॉडल के कारण ढुलाई लागत में कमी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश, विकास और रोजगार सृजन का एक चक्र सुनिश्चित** होगा।
- समग्र योजना को संस्थागत बनाने, विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा प्रगति के एकीकरण और समन्वित परियोजना कार्यान्वयन के लिए **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था** जो भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और 'सहकारी संघवाद' को अपनाता है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



- पीएम गतिशक्ति के तहत **आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए सात इंजनों** द्वारा संचालित किया जाता है यानी: **रेलवे, सड़के, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना** जो आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और रसद ढुलाई दक्षता सुनिश्चित कर रहे हैं।
- पीएम गतिशक्ति में **भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि** जैसी आधारभूत संरचना योजनाएं शामिल हैं।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:

पीएम गतिशक्ति की आवश्यकता क्यों है?

- 2025 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए पूरे देश में मल्टी-मॉडल और अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है।
- इससे परिवहन का एक मिश्रित मॉडल, रसद की कम लागत, बढ़ी हुई निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश प्रगति और रोजगार सृजन का एक चक्र सुनिश्चित होगा।

पीएम गतिशक्ति के बारे में:

- पीएम गतिशक्ति को अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया।
- यह भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए 'समग्र सरकार के विजन' और 'सहकारी संघवाद' का अनुसरण करता है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इस क्रम में सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच एकीकृत योजना है और समकालिक परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना और देश में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कमियों को दूर करना है।

कार्यप्रणाली:

- पीएम गतिशक्ति एक एकल संस्थागत ढांचे के तहत केंद्र सरकार के 27 मंत्रालयों को एक साथ लाकर समग्र सरकार के विजन को बढ़ावा देती है।
- इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 'सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)' का गठन किया गया है। यह भारत सरकार के 23 इंफ्रास्ट्रक्चर और उपयोगकर्ता मंत्रालयों वाला शीर्ष समूह है।
- एक एकीकृत मल्टीमॉडल 'नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG)' को 8 विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व के साथ संचालित किया गया है, जिसमें उनके नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन के प्रमुख शामिल हैं।
- नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन का प्रमुख परियोजनाओं की जांच करता है और उन्हें अनुमोदन के लिए 'सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)' के पास रखता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी पीएम गतिशक्ति तंत्र के माध्यम से एकीकृत योजना और सिंक्रनाइज परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक समान संस्थागत संरचना को दोहराया है।

प्रौद्योगिकी के साथ बुनियादी ढांचे की योजना को उत्प्रेरित करना:

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक प्रौद्योगिकी समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मंच है, जिसमें जीआईएस-आधारित बुनियादी ढांचे, भौगोलिक विशेषताओं और जनसांख्यिकी और निर्णय समर्थन की विभिन्न प्रणालियों की डाटा परतें हैं।
- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना और राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर देश को अपने हरित लॉजिस्टिक्स और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



स्मार्ट होती सड़क अवसंरचना:

परिचय:

- भारत के सड़क अवसंरचना को छह श्रेणियों में बांटा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सड़कों की लम्बाई की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है (संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान विश्व में पहले नंबर पर है)।

देश में सड़कों की वस्तुस्थिति:

- हमने पिछले 28 वर्षों में लगभग 40 लाख कि.मी. नई सड़क बनाई है, जबकि पहले के 40 वर्षों में लगभग 19 लाख कि.मी. सड़कों को जोड़ा गया था। पिछले कुछ वर्षों में सड़क अवसंरचना की वृद्धि काफी तेज और परिवर्तनकारी रही है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 1991 के बाद सबसे अधिक 5.02 प्रतिशत रहा है इसके बाद ग्रामीण सड़कों का 4.67 प्रतिशत रहा है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 144955 कि.मी. है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम को झेलने वाली सड़कों का निर्माण करके कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- भारत में कुल सड़क लंबाई का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है।

भारत में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए किये गए प्रयासः

- मात्रा और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से सड़क आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण चालक रही हैं।
- हाल के तीन दशकों में निम्नलिखित विभिन्न संगठनात्मक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों ने सड़क अवसंरचना को पहले से और सक्षम बनाया हैः
- सड़क विकास और प्रत्यक्ष रोजगार को अलग करनाः
 - उदारीकरण के पूर्व तक की अवधि में सड़कों के विकास पर योजनाबद्ध रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था (नागपुर योजना (1943-1963) बम्बई योजना (1961-81) लखनऊ योजना (1981-2001)) यह परियोजनाएं प्रत्यक्ष रोजगार सृजन से भी जुडी थीं।

ADDRESS:



- इनके निर्माण में ऐसे तरीके अपनाये गए जिसमें श्रम को ज्यादा भूमिका थी और गुणवत्ता को तरफ कम ध्यान गया था।
- 1990 के दशक के उत्तरार्ध में इस मानसिकता में बदलाव आया और सड़क निर्माण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपकरण इस्तेमाल किये जाने लगे।
- **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का निर्माण:**
 - राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से फरवरी 1995 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत की गई।
 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देता था और इसकी जिम्मेदारी राज्य की होती थी।
- **सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP):**
 - 1996 में ही NHAI के शुरुआती दिनों के दौरान इस पर विचार किया जाने लगा था।
 - प्रारंभिक रियायत समझौते सरकार के अनुरूप थे।
 - उस समय यदि PPP के तहत निर्माण किया भी गया तो वो बाईपास और ओवर ब्रिज जैसे छोटे खंडों के लिए किया गया जहां यातायात जोखिम कम थे।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- **राज्य स्तरीय सड़क विकास निगमों का निर्माण:**

- जैसे ही NHA सक्रिय हुआ, कई राज्यों ने अपने अधीन सड़क विकास के लिए लोक निर्माण विभाग की तुलना में बेहतर संगठनात्मक संस्थानों के गठन के बारे में सोचना शुरू कर दिया।

- **महाराष्ट्र** ऐसा पहला राज्य था जिसने अगस्त 1996 में **महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड** की स्थापना की। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था।

- कुछ राज्य एक्सप्रेसवे मानक सड़कें भी विकसित कर रहे हैं। **उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है।**

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) की शुरुआत:**

- यह परियोजना 1998 में NHA के तहत शुरू की गई थी और परिणामस्वरूप इसे सात चरणों तक बढ़ाया गया, जिसमें कुल **49,260 कि.मी.** की लंबाई शामिल थी।

- इसके तहत उस समय की संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

ADDRESS:



- पहले चरण में चार प्रमुख मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ने वाला चार लेन का स्वर्णिम चतुर्भुज था। दूसरा चरण चार लेन का था, जो देश के दूरस्थ जगहों तक उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों को जोड़ता था।
- 2018 में अधिकांश NHDP परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद, **शेष कार्यों को उससे बड़ी परियोजना भारतमाला के अंतर्गत शामिल** कर लिया गया।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):**
 - यह भारत में सबसे सफल परियोजनाओं में से एक रही है।
 - **इसके तीन कारण हो सकते हैं:**
 - (i) वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर कनेक्टिविटी के लिए गांवों का चयन;
 - (ii) विश्व बैंक सहित स्वतंत्र एजेंसियों की निगरानी; और
 - (iii) इस परियोजना को **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (आपूर्ति पक्ष) के बजाय ग्रामीण विकास मंत्रालय (मांग करने वाले पक्ष) के अधीन** रखना।
- **नए अनुबंध मॉडल और परिसंपत्ति मुद्रीकरण:**
 - पिछले एक दशक में निम्नलिखित मॉडल स्वीकार्य ऑपरेटिंग मॉडल के रूप में उभरे हैं:
 1. इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण (EPC)



2. PPP के माध्यम से निर्माण, संचालन, स्थानांतरण (BOT)

3. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM)

4. टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर (TOT)

➤ हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) में निजी संस्थाओं के लिए बेहतर जोखिम

आवंटन है जिसे टोल राजस्व को आघात लगाए बिना, सड़क का निर्माण और संचालन करना होगा। इसके अलावा, पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। शेष 60 प्रतिशत का भुगतान निजी कंपनियों को 30 वर्षों में छमाही किस्त में किया जाता है।

➤ टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर (TOT) मॉडल में, *निजी कंपनी को रियायती अवधि के दौरान टोल संग्रह और रखरखाव के लिए एक निर्मित सड़क की पेशकश की जाती है।*

● **इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) या FASTAG:**

➤ देश भर में टोल प्लाजा की संख्या तेजी से बढ़ रही है लिहाजा टोल संग्रह में लगने वाले समय और प्रतीक्षा को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) लाना अनिवार्य हो गया था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- 31 मार्च 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की संख्या 96 प्रतिशत तक पहुंच गई।
- विकसित देशों की तरह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की इस तकनीक को और विकसित करना होगा, जिससे टोल के लिए वाहनों को धीमा करने की आवश्यकता नहीं पड़े और अधिकतम गति के साथ चलते हुए भी टोल का भुगतान किया जा सके।

देश भर में सड़क विकास के समक्ष चुनौतियां:

- सड़क के बेहतर डिजाइन और निर्माण पर फोकस:

- सड़क डिजाइन और निर्माण की चली आ रही पद्धति हमारी असुरक्षित सड़कों की सबसे बड़ी वजह है, इससे किसी देश में कई लोगों की जान चली जाती है।
- हालांकि हम सड़क पर तेज गति से चलना चाहते हैं, लेकिन सड़कों के डिजाइन और निर्माण उसके अनुसार नहीं है।
- उदाहरण के लिए, दाएं मुड़ने के लिए शायद ही कोई बफर लेन होती है, जिससे ट्रैफिक को दूसरी तरफ से आ रहे ट्रैफिक का इंतजार करने में मदद मिलती है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- निर्माण के दौरान यातायात दूसरी तरफ मोड़ने (डायवर्जन) के लिए बनाई गई सड़क खराब गुणवत्ता की हैं, जिससे वाहनों की गति धीम होने के कारण जाम लग जाता है।
- सड़क उपयोगकर्ता को उनकी ड्राइविंग गति में बदलाव के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त साइन बोर्ड नहीं लगे होते हैं।
- इसी तरह वाहन उपयोगकर्ता की सहूलियत और अपेक्षाओं के अनुरूप सड़क के किनारे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है।

● शहरी सड़कें:

- जहां लंबी दूरी और ग्रामीण सड़कों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं शहरी सड़कों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- इसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में जाम लग जाता है और सड़कों पर वाहन की गति धीमी हो जाती है, जिससे समय की काफी बर्बादी होती है।
- शहरों में पार्किंग एक महत्वपूर्ण मसला है।
- शहरी सार्वजनिक परिवहन के साथ भी उचित समन्वय स्थापित करने की जरूरत है।

ADDRESS:



रेल अवसंरचना:

परिचय:

- भारत में रेलवे माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। यह देश के सुदूर कोने से लोगों को एक साथ जोड़ता है और व्यापार, दर्शनीय स्थलों को यात्रा, तीर्थ यात्रा और शिक्षा के संचालन को संभव बनाता है।



- भारतीय रेल पिछले 170 से अधिक वर्षों के दौरान एक महान एकीकृत शक्ति रही है। इसने देश के आर्थिक जीवन को एक सूत्र में पिरोया है और उद्योग तथा कृषि के विकास को गति देने में मदद की है।

रेल की विकास यात्रा:

- 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर के मार्ग पर चली। अब भारतीय रेल 68,043 किलोमीटर की लंबाई वाले मार्ग में फैले 7308 स्टेशनों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में विकसित हो गया है।

ADDRESS:



- 31 मार्च 2022 तक रूट किलोमीटर का लगभग 74.06 प्रतिशत और रनिंग ट्रैक किलोमीटर का 80.38 प्रतिशत और कुल ट्रैक किलोमीटर का 78.46 प्रतिशत विद्युतीकृत है।
- रेलवे नेटवर्क को 17 जोन में बाँटा गया है।

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमः

- रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित 12 केंद्रीय सार्वजनिक निगम कार्यरत हैं:
 1. राइट्स लिमिटेड
 2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
 3. इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRFC)
 4. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR),
 5. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRCL)
 6. मुंबई रेल विकास कारपोरेशन लिमिटेड (MRVC)
 7. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC)
 8. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RCIL)

ADDRESS:



9. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)
10. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
12. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

अनुसंधान एवं विकास:

- लखनऊ में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास विंग है।
- यह तकनीकी मामलों में भारतीय रेलवे के सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- आरडीएसओ और आईआईटी खड़गपुर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए रूट कंट्रोल चार्ट तैयार करने के लिए स्वदेशी रूप से स्वचालन उपकरण (सिगडेट) विकसित किया है।

रेलवे वित्त:

- वर्तमान में रेल बजट भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का एक हिस्सा है। लेकिन 1924 के पृथक्करण कन्वेंशन के कारण 1924-25 से रेलवे बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया जा रहा था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- सरकार ने बजट वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि एकीकृत बजट रेलवे के मामलों को केंद्र में लाता है और सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- इस विलय से राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के बीच मल्टीमॉडल परिवहन योजना की सुविधा मिलेगी।

रेलवे विद्युतीकरण:

- भारतीय रेल की शत प्रतिशत विद्युतीकरण नीति को देश के संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- कच्चे तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा भुगतान को बचाने के लिए सरकार ने शुरू में रेलवे विद्युतीकरण की दर को बढ़ाया।
- इलेक्ट्रिक इंजनों की उच्च शक्ति माल ढुलाई और यात्री ट्रेनों दोनों के लिए औसत गति और लोडिंग को बढ़ाती है जो बदले में रेलवे को आधुनिक बनाने और आर्थिक विकास का समर्थन करने का एक जबरदस्त अवसर प्रदान करती है।
- विद्युतीकरण कार्बन फुटप्रिंट को कम करके स्वच्छ परिवहन प्रदान करने और देश को पर्यावरण के अनुकूल हरित और स्वच्छ परिवहन का साधन प्रदान करने की अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- मार्च 2023 तक, भारतीय रेल पर विद्युतीकरण को कोंकण रेलवे सहित 58812 RKM तक बढ़ा दिया गया है। यह कुल BG रेलवे नेटवर्क का 90 प्रतिशत है।

रेल पर्यटन:

- भारतीय रेल देश भर के विभिन्न पर्यटन स्थलों को रेल द्वारा जोड़कर देश में पर्यटन का प्रमुख प्रेरक है।
- भारतीय रेल ने पर्यटन क्षेत्र और अन्य संभावित सेवाओं के पेशेवरों के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य ने से 'भारत गौरव ट्रेन' नीति के तहत थीम आधारित ने पर्यटक सर्किट ट्रेन शुरू की हैं।
- उक्त नीति के तहत, राज्य में सरकारें राज्य पर्यटन विकास निगम या कोई अन्य संभावित सेवा प्रदाता अपनी पसंद के किसी भी गंतव्य को कवर करते हुए थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन चला सकते हैं।

राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) 2030:

- भारतीय रेल ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) 2030 तैयार की है। यह योजना 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली बनाने की है।

ADDRESS:



- **योजना का उद्देश्य:**

- इस योजना का **उद्देश्य 2030 तक ऐसी क्षमता का निर्माण करना है, जो मांग से अधिक रहे तथा 2050 तक की मांग में वृद्धि संबंधी जरूरतों को पूरा करे।**
- इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के एक अंग के रूप में 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी वर्तमान के 27% से बढ़ाकर 45% करना है।
- मालगाड़ियों की औसत गति 50 कि.मी. प्रति घंटे तक बढ़ाकर माल ढुलाई के समय को काफी हद तक कम करना।
- रेल परिवहन की कुल लागत को लगभग 30% कम करना और उससे अर्जित लाभों को ग्राहकों को हस्तांतरित करना।

- **विजन 2024:** राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में **2024 तक:**

- शत-प्रतिशत विद्युतीकरण,
- भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी-ट्रैकिंग,
- दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर 160 कि.मी. प्रति घंटे की गति का उन्नयन,
- अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज- स्वर्ण विकास (GQ/GD) मार्गों पर गति का 130 कि.मी. प्रति घंटे तक उन्नत करना और

ADDRESS:



- सभी GQ/GD मार्गों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इसे लॉन्च किया गया है।

वंदे भारत ट्रेन:

- भारत में 'मेक इन इंडिया' की सफलता की कहानी के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में, भारतीय रेल ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की।
- पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली- कानपुर - इलाहाबाद- वाराणसी मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई थी।
- यह ट्रेन विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित भारत की पहली सेमी-हाईस्पीड ट्रेन है।
- यह शीघ्र रफ्तार पकड़ने के कारण यात्रा के समय को 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक कम कर देगा।
- 28 जुलाई 2023 तक 50 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं भारतीय रेल द्वारा परिचालित की जा रही हैं।
- वंदे भारत ट्रेनों ने आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा प्रदान की है। यात्रियों के लिए अच्छा अनुभव, उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा इस ट्रेन की पहचान है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)